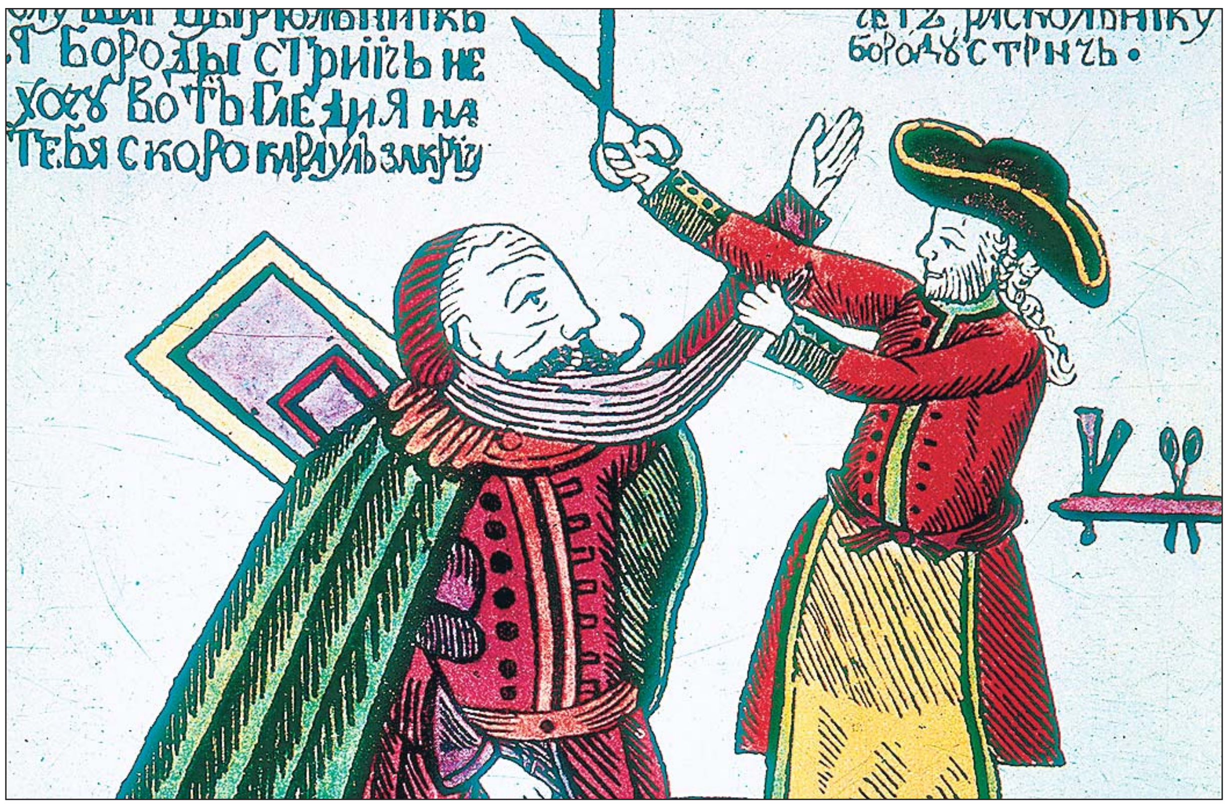

रुस में ज़ारशाही का शासक पीटर द ग्रेट यूरोपियन मानदंडों के अनुरुप रुस का आधुनिकीकरण करने पर इस कदर आमादा था कि उसने सभी पुरुषों को लम्बे ओवरकोट नहीं पहनने और दाढ़ी कटवाने के आदेश जारी कर दिए थे। जब उसके कठोर आदेश पर काफी हंगामा हुआ तो उसने एक "बिअर्ड टैक्स" का आदेश जारी किया, जिसके अनुसार, जो भी पुरुष दाढ़ी रखना चाहता था उसे टैक्स देना पड़ता था। दाढ़ी रखने की रुस के इतिहास की पुरानी और गौरवमयी परम्परा थी। दाढ़ी -मूंछ इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि, 12 वीं सदी में ऐसे कई कानून थे जिनमें दाढ़ी -मूंछ के साथ छेड़छाड़ करने पर जुर्माना देना पड़ता था, और यह जुर्माना घोड़ा चुराने या उंगली काटने से भी चार गुना अधिक था। दाढ़ी -मूंछ आदमी की प्रतिष्ठा और मर्दानगी का प्रतीक मानी जाती थी, इसका सम्बंध धर्म से था दाढ़ी -मूंछ कटवाने को ईसानिंदा के समकक्ष माना जाता था। जब पीटर द ग्रेट ने रुसी समाज को यूरोपियन तर्ज पर बदलने की कोशिश की तो उसने विरोध की संभावना को कम आंका। शायद उसकी शुरुआती सोच ने उसे कठोर कानून बनाने को प्रेरित किया था। यूरोप के दौरे से लौटने के बाद ज़ार के सम्मान में समारोह आयोजित हुआ। ज़ार ने समारोह में आए मेहमानों की दाढ़ी खुद काट दी। दाढ़ी प्रतिबंध लागू करने के लिए उसने पुलिस को अधिकार दिया कि, जो लोग दाढ़ी नहीं काट रहे हैं उनकी जबर्दस्ती दाढ़ी काट दी जाए। पर पीटर को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसकी नीति किसी को पसंद नहीं। सामन्तों, किसानों व रुसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने जब इसका भारी विरोध किया तो उसे पीछे हटना पड़ा और तब उसने बिअर्ड टैक्स चालू किया। टैक्स की राशि व्यक्ति की स्थिति के अनुसार होती थी। अमीर व्यापारी को 100 रुबल सालाना, शहर के आम लोगों को 60 रुबल सालाना तथा किसानों को शहर आने पर शुल्क देना पड़ता था। जो लोग टैक्स देते थे उन्हें बिअर्ड टोकन साथ रखना पड़ता था। सामान्तों को सिल्वर टोकन, आम लोगों को तांबे का टोकन दिया जाता था। यह टैक्स काफी अलोकप्रिय हुआ, जिसे 1722 में कैथरीन द ग्रेट ने रद्द कर दिया।

'राजस्थान में भी 10-10 करोड़ रूपए तो बंट चुके थे, पता नहीं क्या हुआ बाद में'

मु.मंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर कटाक्ष किया

दिल्ली/जयपुर, 21 जून (का.प्र.)। मंगलवार को महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासी उठापटक के बहाने एक बार फिर सियासी संकट को याद करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर विधायकों की खरीद के रेट बताए। राजस्थान के सियासी संकट पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए तो बंट चुके थे। पता नहीं क्या हुआ बाद में फिर। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि राजस्थान के हमारे विधायक 34 दिन तक मेरे साथ रहे। अंदर थे, कुछ नहीं मिला। बाहर निकलते ही 10 करोड़ रुपए की ऑफर थी। तब भी कोई नहीं गया। अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा कि तीनों सीटें हम जीते हैं।

दिल्ली से जयपुर लौटते समय मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि हम जो बार-बार कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कब्जा कर लिया। एक-एक विधायक को 35-35 करोड़ रुपए का ऑफर हम सुनते हैं। एक-एक विधायक से 25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए के सौदे हुए। हर राज्य की अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। वो एक नया प्रयोग था उनका। उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। मध्य प्रदेश में इन्होंने जो कुकर्म किया, उसको हम समझ गए थे टाइमली। हमने पूरा उसी ढंग से बिहेव किया। उससे बाद में हम कामयाब हो गए।

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बात करते हुए गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो षड्यंत्र किया गया, मैं सुन रहा हूं। विधायकों को सूरत लेकर चले गए हैं। आप सोच लीजिए कि ये क्या गवर्नेंस कर रहे हैं देश के अंदर? अब महाराष्ट्र का देखिए आप। पता नहीं मालूम करेंगे कि क्या हो रहा है वहां पर। ये उनका जो प्रयास है सरकार गिराने का ये तो एक प्रकार से दुनिया के सामने ओपन हो गया है। इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया है, कैसे किया गया, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होगी, क्या सौदे हो रहे होंगे, वो तो वो जानें और उनकी आत्मा जाने।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उस वक्त में भी जो तमाशा हुआ था, वो सबके सामने है। अचानक सुबह साढ़े छह बजे शपथ करवा दी गई। बधाइयां मिलने लग गईं। जो शपथ लेने वाले थे मिस्टर फडणवीस, उन्होंने वापस ट्वीट किया कि मोदी है तो मुमकिन है।

मतलब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जुर्म भी है, अन्याय भी है, अत्याचार भी है, उत्पीड़न भी है, सब कुछ संभव है। बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी। तब से ही उनके दिल में ये टीस थी कि कब हमें मौका लगे, कब हम ईडी का उपयोग करें, डराएं - धमकाएं सीबीआई से, इनकम टैक्स से और वो ही देख रहे हैं आप। 2-2 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। जमानत तक नहीं होने दी जा रही है, तो ये तमाम षड्यंत्र हैं। लोकतंत्र को नष्ट करने का, खत्म करने का।

- गहलोत के अनुसार मध्य प्रदेश में तो एक-एक विधायक से 25-30-35 करोड़ तक में सौदे हुए।
- ''ई.डी. और इनकम टैक्स का मिसयूज़ हो रहा है, न्याय के लिए कहां जाएं, जुडिशिअरी खुद दबाव में है।''

गहलोत ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ। अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सरकारें गिराने के षडयंत्र चल रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ईडी और इनकम टैक्स का मिसयूज हो रहा है। जब न्याय नहीं मिलता है तो आदमी जूडिशियरी में जाता है। अब जूडिशियरी खुद दबाव में है।

अगर वही दबाव में हो तो आदमी कहां जाए? यह बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। ये फासिस्ट लोग हैं। केवल लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए हैं। इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। केवल लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति कर रहे हैं।

शिव सेना नेता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राउत को ठाकरे का मुख्य सहयोगी माना जाता है। आज भी राउत ने सेना की तरफ से पी.आर अभियान संभाला और कहा कि शिंदे शिव सेना के प्रति निष्ठावान हैं और संकट को जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। विधानसभा में अगर विश्वास मत हुआ तो ठाकरे को हटाने के लिए भाजपा को 37 विधायक और चाहिए उसके पास अपने 106 विधायक हैं। जी-22 के बिना ठाकरे की सरकार बहुमत के एकदम करीब आ गई है जी-22 असल में कांग्रेस के असंतुष्टों के प्रयुक्त शब्द है, पर सेना के जी-22 में मंत्री हैं।

शिंदे ठाणे के एक जन नेता हैं और नगर विकास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री है।

यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संरक्षित सिन्हा पार्टी के महासचिव तथा प्रवक्ता बन गये थे। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए सिन्हा के नाम की घोषणा होने के बाद, उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टी.एम.सी. में मुझे जो प्रतिष्ठा एवं सम्मान दिया, उसके लिये मैं उनका "आभारी" हूँ। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अब एक बड़े राष्ट्रीय हित के लिये काम करने का समय आ गया है तथा "मुझे विपक्ष की एकता के एक बहुत बड़े काम की खातिर, पार्टी से हटकर काम करना होगा।" उन्होंने कहा कि "मुझे पूरा यकीन है कि वे (बनर्जी) इस कदम का समर्थन करेंगी।"

एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार द्वारा संसद के उप भवन में बुलाई गई एक मीटिंग में एकत्रित हुये विपक्ष के नेता सिन्हा के नाम पर एकमत से तैयार हो गये। विपक्ष के चयन की सुई सिन्हा तक तक पहुँची, जब तीन हस्तियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिये विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। ये तीन हस्तियाँ थीं- पूर्व केन्द्रीय मंत्री शरद पवार, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला तथा पूर्व राज्यपाल एवं महात्मा गांधी के पौत्र एवं देश के गवर्नर जनरल रहे सी. राजगोपालाचारी के दोहिते, गोपाल कृष्ण गांधी।

विपक्ष के संयुक्त बयान का वाचन करते हुये, कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा, "हमने निर्णय लिया है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिये (विपक्ष के) एक साझा प्रत्याशी का चयन किया जाये तथा मोदी सरकार को और अधिक नुकसान करने से रोका जाये। आज यहाँ हुई मीटिंग में, हमने साझा उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा का चयन किया है। हम सभी विपक्षी दलों से यशवंत सिन्हा को वोट देने की अपील करते हैं।"

इस साझा बयान में भाजपा तथा उसके मित्र दलों से भी सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की गई, जिससे देश को "निर्विरोध निर्वाचित योग्य राष्ट्रपति मिल सके।" यशवंत सिन्हा के प्रचार के संचालन के लिये एक कमेटी गठित कर दी गई है।

रमेश ने कहा, "हमें दुख है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिये सर्वसम्मति की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।"

साझा बयान को पढ़ते हुये, उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिये बनी विपक्षी एकता आने वाले महीनों में और भी मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी नैशनलिस्ट पार्टी प्रमुख शरद पवार तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुके थे। भाजपा भी आज अपने संसदीय दल की बैठक करेगी, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिये उसके चयन को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

अपनी आत्मकथा "रिलेन्टलैस" में, सिन्हा लिखते हैं कि "मेरे जन्म की तारीख और वर्ष तो समय की भूलभुलैयों में कहीं खो गये", लेकिन मेरे बड़े भाई टुनटुन भैया, जो 1944 में स्कूल में दाखिल कराने के लिये मुझे ले गये थे, ने इसकी प्रविष्टि 6 नवम्बर, 1937 के रूप में करा दी" और यही रिकॉर्डों में उनकी प्रामाणिक जन्म तिथि हो गई। सिन्हा ने स्कूली तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा पटना से ली। 1958 में, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम.ए. किया तथा अपने उसी कॉलेज में 1958 से 1960 तक राजनीति विज्ञान विषय का अध्यापन किया। 1960 में वे आई.ए.एस. अधिकारी बन गये तथा 24 साल के अपने कार्यकाल में विभिन्न पदों पर रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर सिन्हा ने 1984 में आई.ए.एस. की नौकरी से इस्तीफा दे दिया तथा पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में उतर गये। वे 1986 में अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त कर दिये गये तथा 1988 में राज्यसभा के लिये चुन लिये गये। जब वी.पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ तो सिन्हा उसके महासचिव बना दिये गये। वे नवम्बर 1990 से जून 1991 तक चन्द्रशेखर, जिन्होंने जनता दल को तोड़कर, समाजवादी जनता पार्टी बना ली थी, के मंत्रिमण्डल में पहली बार देश के वित्त मंत्री बने।

वे अपने हजारी बाग लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे, जो इस समय झारखंड में हैं। लेकिन 2014 में, भाजपा ने उन्हें हजारी बाग से टिकट देने से इनकार कर दिया। भाजपा ने इस सीट से सिन्हा के पुत्र जयन्त को चुनाव में उतारा था। सिन्हा ने 2018 में पटना के एक समारोह में, सक्रिय राजनीति को छोड़ देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, वे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये तथा पार्टी के उपाध्यक्ष बन गये। मंगलवार को उन्होंने पार्टी से यह कहते हुये इस्तीफा दे दिया कि अब उनके लिये विपक्ष की महान एकता के लिए काम करने का समय आ गया है।

वाजपेयी मंत्रिमण्डल में, वे 1998 से 2002 तक दो बार वित्त मंत्री रहे। 2002 में, उनके और विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पदों में अदला-बदली कर दी गई। संयोग देखिये, सिन्हा के पिता ने उनका नाम प्रसिद्ध राजपूत योद्धा जसवंत सिंह मारवाड़ के नाम पर ही रखा था। अपने छोटे से कार्यकाल के बारे में बात करते हुये, वे प्रायः पूर्व अमेरिकन सैक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पोवेल के साथ रहे अपने बहुत अच्छे तालमेल का जिक्र करते हैं। सिन्हा कहते हैं कि वे ऐसे एकमात्र भारतीय विदेश मंत्री रहे हैं जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति (उस समय जॉर्ज बुश) से मिलने के लिए ओवल ऑफिस में आमंत्रित किया गया था।

जहाँ सिन्हा भाजपा और सक्रिय राजनीति से परे हो गये, उनके पुत्र जयंत भाजपा में ही हैं तथा अपने पिता के पूर्व चुनाव क्षेत्र हजारी बाग से सांसद हैं। पिछली मोदी सरकार में, जयंत केन्द्रीय राज्य मंत्री थे। सिन्हा का विवाह नीलिमा से हुआ था तथा उनके दो पुत्र एवं एक पुत्री है। जहाँ एन.डी.ए. के समक्ष इस चुनाव में छोटी-मोटी मुश्किल के अलावा कोई परेशानी नहीं है, वहीं सिन्हा विपक्ष- दोनों के लिये बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एक नैतिक रूख प्रदर्शित करते हुये यह चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम कुछ भी क्यों न रहे, लेकिन यह बड़ा रोचक रूप लेने जा रहा है।

इस तथ्य के बावजूद कि संख्या बल सत्तारूढ़ एन.डी.ए. के प्रत्याशी के पक्ष में ही है, सिन्हा जो लोकतंत्र एवं संविधान के सुस्पष्ट प्रवक्ता तथा उनके घोर समर्थक हैं, अगले राष्ट्रपति के लिये इस चुनावी लड़ाई में जान डाल देंगे। नये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 15 जून को शुरु हो गई थी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 जून है। अगर जरूरी हुये तो चुनाव 18 जुलाई को होंगे तथा मतगणना 21 जुलाई को होगी।

थानाधिकारी-कांस्टेबल के बीच समलैंगिक संबंध बने

फिर संबंध ब्लैक मेलिंग में तब्दील हुए

नागौर, 21 जून (निसं)। नागौर जिले की खाकी को शर्मसार करने का मंगलवार को मामला सामने आया है। रोजमर्रा की जिंदगी में महिला एवं पुरुष के बीच प्रेम संबंध होना आम बात हो गई है मगर दो पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर इस हद तक पहुंच जाए की परिणाम शर्मसार कर देने वाले हो जाए।

मामला खींवसर थानाधिकारी और कांस्टेबल के बीच का है और फिर दोनों के बीच समलैंगिक संबंध तक बन गए मगर कांस्टेबल ने जब थानाधिकारी को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आ गया।

खींवसर थानाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। उधर नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच नागौर वृत्ताधिकारी को सौंपी गई है।

- खीवसर एस.एच.ओ. ने डेगाना में तैनात कांस्टेबल के खिलाफ कराई एफ.आई.आर.।
- नागौर एस.पी. ने तुरंत कार्यवाही कर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया ।

प्रकरण के अनुसार डेगाना थाने में तैनात एक कांस्टेबल की खींवसर थानाधिकारी से फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोस्ती प्रेम में बदल गई।

दोनों के बीच न्यूड चैटिंग होने लगी और फिर समलैंगिक संबंध बन गए। बाद में कांस्टेबल थानाधिकारी को ब्लैकमेल करने लगा। बताया जा रहा है कि, उसने थानाधिकारी से ढाई लाख रुपए ऐंठ लिए और लाखों रुपयों की डिमांड व एक कार तक मांगने लगा। इससे परेशान खींवसर थानाधिकारी एसपी के समक्ष उपस्थित हुए और लिखित शिकायत पेश की।

बताया जाता है कि कांस्टेबल ने वीडियो चैटिंग को रिकॉर्ड कर लिया तथा उसके पास दोनों के कई अश्लील वीडियो थे और वो उसे वायरल करने की धमकी देकर थानाधिकारी से रूपए ऐंठने लगा।

इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डेगाना थाने में तैनात कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है।

उधर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए तुरंत प्रभाव से खींवसर थानाधिकारी व डेगाना कांस्टेबल दोनो को निलंबित कर दिया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।

अग्निपथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि, मुझे लगता है कि विरोध करना अपनी आवाज़ उठाना न्यायोचित है और लोकतंत्र में इसकी अनुमति है लेकिन यह गुंडागर्दी, हिंसा इसकी ना तो अनुमति है और ना ही बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया "जहां तक रेजीमेंटों का प्रश्न है, दो बातें समझना जरुरी है। रेजीमेन्टों की अवधारणा से कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। --- वे (रेजीमेन्ट) बनी रहेंगी।-- रेजीमेन्ट व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है।---"

इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री एम.एल. खट्टर ने कहाः "वे अग्निवीर (4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीर), जो हरियाणा सरकार की नौकरियों पाना चाहेंगे, को गारंटी शुदा नौकरियाँ दी जायेंगी। जो अग्निवीर चाहेंगे, वे ग्रुप सी की नौकरियों के किसी भी केडर में जा सकेंगे। अन्यथा स्थिति में, हमारे पास पुलिस की नौकरी हैं, जो उन्हें दे दी जायेंगी।

राष्ट्रपति पुतिन की बेशुमार सम्पत्ति व धन?

लंदन, 21 जून (वार्ता)। रूस के ईमेल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी साढ़े चार अरब डॉलर से अधिक की संपत्तियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। द गार्जियन के अनुसार एक डिजिटल पेपर के सबूतों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा कथित तौर पर उपयोग किए जाने वाले हॉलिडे होम और अन्य संपत्तियों की एक लम्बी सूची मिली है। जो उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों, कंपनियों और धार्मिक संस्थायें के स्वामित्व में हैं वह सभी एक ही एल.एल.सी.आई.एन. वेस्ट डॉट आर.यू. नाम के एक ही ईमेल डोमेन से जुड़ी है। जानकारी में आये ईमेल एक्सचेंजों से पता चलता है कि इन संपत्तियों को रखने और प्रबंधित करने वाली अलग-अलग संस्थाओं के निदेशक और प्रशासक दैनिक व्यावसायिक मामलों पर उसी तरह चर्चा करते है जैसे कि वे एक ही संगठन का हिस्सा हों।

'हमें भी सुनें'...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे हिंसक प्रदर्शनों पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका में आरोप लगाया गया है कि केन्द्र सरकार सेना में चयन की 100 साल पुरानी प्रक्रिया को खत्म कर दिया है जो कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है तथा इस पर संसद की अनुमति भी नहीं ली गई है।

कमलनाथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगलवार को जोर देते हुये कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपना पंचवर्षीय कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अगर गठबंधन टूटता है तो उनकी पार्टी एन.सी.पी. भाजपा के साथ चली जायेगी।

नक्सली हमले में 3 सी.आर.पी.एफ. जवान शहीद

रायपुर, 21 जून। छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर सी.आर.पी.एफ. टीम के ऊपर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में तीन जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हमला सी.आर.पी.एफ.-19 बटालियन की आर.ओ.पी. पार्टी पर किया गया है। हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। यह हमला ओडिशा के नौपाड़ा जिले में हुआ है। नक्सलियों ने हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब सी.आर.पी.एफ. जवान सड़क बनाने के काम में लगे लोगों को सुरक्षा देने के लिए निकले थे।

इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा जवानों के ऊपर हमला कर दिया। सी.आर.पी.एफ. से मिली सूचना के मुताबिक जवानों के ऊपर यह हमला दोपहर करीब 2.30 बजे हुआ। इस हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. जवानों की पहचान हो गई है।

प्रदेश में एक जुलाई से स्कूल शुरु

माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने यह कैलैण्डर जारी किया

बीकानेर, 21 जून (कासं)। राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 24 जून से शुरू हो जायेंगे लेकिन रैगुलर क्लासेज़ एक जुलाई से शुरू होंगी। टीचर्स को 24 जून से स्कूल पहुंचना होगा। वहीं सभी स्कूलों में एडमिशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 का कलैण्डर जारी करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी ईयर कलैण्डर के अनुसार नया सत्र 2022-2023 24 जून से आरम्भ होगा तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ होगी। प्रवेशोत्सव दो चरणों में चलाया जायेगा। प्रथम चरण 24 जून 2022 से प्रारम्भ होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी। वहीं व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नये विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 21 से 30 जून तक की जायेगी।

- 24 जून से आना होगा टीचर्स को, एडमिशन की लास्ट डेट्स 15 जुलाई।

इस स्कूलों में मध्यावधि छुट्टियां 19 से 31 अक्टूबर 2022 तक होगी। जबकि सर्दी की छुट्टियां 25 दिसम्बर, 2022 से 5 जनवरी 2023 तक होंगी। वार्षिक व बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा के उपरान्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगला नया सत्र 1 मई 2023 से प्रारम्भ होगा तथा 1 मई से 16 मई, 2023 तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण का आयोजन होगा। गर्मी में एक अप्रैल से तीस सितम्बर तक सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर एक बजे तक स्कूल खुलेंगे। कुल साढ़े पांच घंटे स्कूल लगेगी और 35 मिनट का एक पीरियड होगा।

सर्दियों में एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह दस बजे से चार बजे तक स्कूल लगा करेंगे। कुल छह घंटे पढ़ाई होगी। एक अप्रेल से तीस सितम्बर तक सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक स्कूल लगेंगे। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक फर्स्ट टेस्ट होंगे। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच सैकंड टेस्ट होंगे।

10 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा होगी। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक थर्ड टेस्ट होंगे। 6 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच फाइनल एग्ज़ाम होंगे।

महाराष्ट्र में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नारायण राणे पार्टी से उस समय निकाल दिये गये थे, जब उन्होंने उद्धा ठाकरे के नेतृत्व को उस समय चुनौती दी थी, जब उद्धव 2003 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिये गये थे। जहाँ शिवसेना इन सब बगावतों को सफलतापूर्वक झेल चुकी है, वहीं शिन्दे का विरोध, एम वी ए सरकार के सम्भावित पतन का कारण बन सकता है।

ईस्टर्न कैनाल प्रोजैक्ट पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत व पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट आमने-सामने

सचिन पायलट से चूक हो गई, मध्यप्रदेश जैसा फैसला हो गया होता तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजैक्ट पर काम चालू हो चुका होता- गजेन्द्र सिंह

- पायलट ने पलटवार किया- ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट में बीजेपी ने राजस्थान से वादाखिलाफी की, वो अपनी विफलता का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं।
- सरकार की कमी को दूर करने के बजाय गलती छिपाने के लिए मंत्री जुटे, गलती तो जनता से हो गई कि, वह भाजपा के झूठे वादों में फंस गई- पायलट।

जयपुर, 21 जून (का.प्र.)। जुलाई 2020 के दौरान राजस्थान में पैदा हुए राजनीतिक संकट पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के मौका चूकने की बात की और कहा कि उस समय सचिन पायलट से चूक हो गई, उस समय राजस्थान के विधायक मध्यप्रदेश जैसा फैसला ले लेते तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट पर काम चालू हो गया होता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिए गए इस बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि जनता समझ गई है, अब वह आपको चुनने की चूक नहीं करेगी और झूठे वादों में नहीं फंसेगी।

गजेंद्र शेखावत के आरोपों पर सचिन पायलट ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ई.आर.सी.पी.) में बीजेपी ने राजस्थान के साथ वादाखिलाफी की है। वे अपनी विफलता का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद शेखावत अपने गृह राज्य की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने मंच से घोषणा की थी कि एनईआरसीपी प्रोजैक्ट शुरू किया जाएगा। सरकार की कमी को दूर करने की बजाय मंत्री उस गलती को छिपाने में जुटे हुए हैं। गलती तो जनता से हो गई कि वह बीजेपी के झूठे वादों में फंस गई।

पायलट ने कहा कि केंद्र के मंत्री तोते की तरह झूठा प्रचार करने में लगे हैं। पहले किसान कृषि बिल की पूरी सरकार ने तोते की तरह प्रशंसा की और बाद में माफी मांग कर बिल वापस ले लिया, लेकिन हमने इतने किसानों को खोया, इसे देश माफ नहीं करेगा। अब अग्निपथ योजना में केंद्र सरकार ने जिस तरह से नौजवानों के साथ छल किया है, उससे पूरे देश का मनोबल कम हुआ है। भारत माता की सेवा करने वाले नौजवान पूरे देश में आक्रोशित हैं तो केंद्र के सभी मंत्री और नेता फिर तोते की तरह योजना का झूठा प्रचार करने में लगे हैं।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चौमूं कस्बे में हुई एक सभा में कहा था कि राजस्थान में सचिन पायलट से चूक हो गई। यदि 2020 में मध्यप्रदेश के विधायकों ने जैसा फैसला किया, उसी तरह राजस्थान में हो गया होता तो आज 13 जिले प्यासे नहीं होते और ईस्टर्न कैनाल प्रोजैक्ट पर काम चालू हो चुका होता। शेखावत ने कहा कि गहलोत ईआरसीपी पर केवल राजनीतिक फायदे के लिए कुंडली मारकर बैठे हैं। राजस्थान सरकार को 13 जिलों के प्यासे कंठो की प्यास बुझाने के लिए प्रोजैक्ट में संशोधन करके भारत सरकार को भेजना है। शेखावत ने कहा कि सरकार संशोधन करके आज भेज दे, तो 2 महीने में इस योजना को लागू करवा दूंगा। अगर ये सरकार दो महीने में संशोधन नहीं भेजे तो आप 2023 में इनको भेज देना। उसके बाद में अपनी बीजेपी सरकार आएगी, वो इसको लागू करवा देगी। इन 13 जिलों के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार केवल राजनीति करना चाहती है। शेखावत ने कहा कि गहलोत जब मुख्यमंत्री बने और ईआरसीपी पर चर्चा की, तो सबसे पहली आपत्ति मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी। 2019 में जब मैं जलशक्ति मंत्री बना तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मंत्रियों-अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारी तो आए, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्रियों को शायद मेरे ऑफिस में आने में डर लगता है।

शेखावत ने कहा कि राजस्थान का कोई मंत्री और संतरी मेरे ऑफिस में नहीं आता है। मैंने 7 बार मीटिंग बुलाई, मंत्री नहीं आए। सातों बार अधिकारियों के साथ चर्चा की कि इसका रास्ता निकलना चाहिए। मध्यप्रदेश को सहमत किया और राजस्थान सरकार को चिट्ठी भेजी कि आप 75 प्रतिशत डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाकर भेजो। मैं तुरंत ही इसको स्वीकृत कर दूंगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600